the matter; if so, what programme has now been formulated to deal with mfiltrations from Bangladesh and also the situation arising therefrom?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AF FAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b) Government have been receiving reports from various sources expressing serious concern about the problem of infiltration of Bangladeshi nationals into India. The Conference of Chief Ministers held in September 1992 under the Chairmanship of the Union Home Minister comprehensively discussed the various issues pertaining to this problem. The Conferende passed a Resolution identifying various actions which need to be taken to deal with the problem. A series of steps have been taken by the Government in this regard. The measures include iaising of additional battallions of Border Security Force to reduce the caps between the border outposts, intensification of patrolling both on the land and the riverine border, accelerated programme of construction of border roads and fencing increase in the number of OP Towers, provision of surveillance equipments etc. The matter has also been taken up with the Government of Bangladesh on various oecasipns.

दिल्ली पुलिस को राशन भत्ता दिया जाना

3649. श्री सत्य प्रकाश मालवीय:
श्री अनन्तराम जायसवाल: :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस की राशन भत्ता से संबंधित मांग केन्द्रीय सरकार के पास काफी समय से लंबित पड़ी है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की यह मांग स्वीकार कर दी है और यह राशन भत्ता स्वयं देने के लिये तैयार है परन्तु इसने इस मामले में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार के इंकार या अनिर्णय से दिल्ली पुलिस के जवानों और उनकी कार्यकुशलता तथा मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस के राजपत्रित कर्मचारियों को राशन भत्ते की स्वीकृति हेतु एक प्रस्ताव, दिल्ली प्रशासन द्वारा सरकार के पास भेजा गया था । इसकी जांच की गई और जून, 1994 में इसे वित्तीय कठिनाईयों की वजह से अस्वीकृत कर दिया गया था ।

यह भी निर्णय लिया गया था कि इस मुद्दे पर समग्रता-पूर्वक विचार करने के लिये इसे पांचवें वेतन आयोग के पास भेजा जाये ।

Directions to CBI a TADA Court

3650. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to Btate:

(a) whether a designated TADA Court of Shahadara has directed the Central Bureau of Investigation to immediately complete investigations against certain Persons who have allegedly harboured Dubai based don, Dawood Ibrahim's henchmen in Delhi as repoited in 'The Hindustan Times" Of the 28th January, 1995;

(b) if so, what, are the facts and details of the matters referred to in the above period: